

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

ग्रन्थालय

EXTRAORDINARY

भाग II—बाण 3—उपलब्ध (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

मं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31, 1976/माघ 11, 1897

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31, 1976/MAGHA 11, 1897

इस भाग में बिन्न पृष्ठ संख्या दो जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 1976

G.S.R. 55(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:

Whereas, I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, have received a report from the Governor of the State of Tamil Nadu and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

- (c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—
- (i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;
 - (ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:—
so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;
so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;
articles 163 and 164;
clause (3) of article 166;
article 167;
so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;
clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of article 174;
articles 175 to 178 (both inclusive);
clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article;
articles 180, 181 and 182, clause (c) of article 183 and the proviso thereto;
article 185;
so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;
so much of article 188 as relates to a member of the Legislative Assembly;
articles 189, 193 and 194;
so much of article 195 as relates to the salaries and allowances of Members of the Legislative Assembly;
articles 196 to 198 (both inclusive);
clauses (3) and (4) of article 199;
so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;
articles 208 to 211 (both inclusive);
the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and
so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;
 - (iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved;
 - (iv) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament and, in particular, references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively:

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153; articles 153 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (1) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

- (v) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution and the Madras General Clauses Act, 1891 (Madras Act 1 of 1891) as in force in the State of Tamil Nadu, and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

NEW DELHI;

FAKHRUDDIN ALI AHMED,

*The 31st January, 1976.**President.*

[No. V/11013/2/TN/76-S&P(DV)]

NEW DELHI;

S. L. KHURANA, Secy.

The 31st January, 1976.

ORDER

New Delhi, the 31st January, 1976

G.S.R. 56(E).—The following Order by the President is published for general information:

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this 31st day of January, 1976 by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Tamil Nadu and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

NEW DELHI;

FAKHRUDDIN ALI AHMED,

*The 31st January, 1976.**President.*

NEW DELHI;

S. L. KHURANA, Secy.

The 31st January, 1976.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1976

सां. का० नि० ३५ (झ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वेशाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है :—

यत् मुझे, भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को तभिल नाड़ राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इस रिपोर्ट तथा मुझे प्राप्त अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उपन्ह हो गई है, जिसमें राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात “संविधान” कहा गया है) के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ;

अतः अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उद्घोषणा करता हूँ कि मैं—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित, तथा उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं सम्भालता हूँ ;

(ख) घोषित करता हूँ कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियां मंसद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होगी; और

(ग) निम्नलिखित आनुबंधिक और पारिणामिक उपबन्ध अरता हूँ जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मुझे आवश्यक या वाल्नीय प्रतीत होते हैं; अर्थात् :—

(i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खण्ड (क) के आधार पर मेरे द्वारा सम्भाले गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक कि मैं ठीक समझू उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा ;

(ii) उक्त राज्य के सम्बन्ध में संविधान के निम्नलिखित उपबन्धों के प्रवर्तन को एतद्वारा निलम्बित किया जाता है, अर्थात् :—

अनुच्छेद 3 के परातुक का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल को निदेश करने से है;

अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) का उतना भाग जिसने का सम्बन्ध भारत के नियंत्रक और महानिवापरीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है;

अनुच्छेद 163 और 164;

अनुच्छेद 166 का खण्ड (3);

अनुच्छेद 167;

अनुच्छेद 169 के खण्ड (1) का उतना भाग जिसने का सम्बन्ध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प को पारित करने से है;

अनुच्छेद 174 का खण्ड (1) और खण्ड (2) का उप-खण्ड (क);

अनुच्छेद 175 से 178 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं);

अनुच्छेद 179 के खण्ड (ख) और (ग) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक;

अनुच्छेद 180, 181 और 182, अनुच्छेद 183 का खण्ड (ग) और उसका परन्तुक;

अनुच्छेद 185;

अनुच्छेद 186 का उतना भाग जिसने का सम्बन्ध विधान सभा के उपाध्यक्ष के बेतनों और भत्तों से है;

अनुच्छेद 188 का उतना भाग जिसने का सम्बन्ध विधान सभा के सदस्य से है;

अनुच्छेद 189, 193 और 194;

अनुच्छेद 195 का उतना भाग जिसने का सम्बन्ध विधान सभा के सदस्यों के बेतनों और भत्तों से है;

अनुच्छेद 196 से 198 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं);

अनुच्छेद 199 के खण्ड (3) और (4);

अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) का उतना भाग जिसने का सम्बन्ध विधान सभा के उपाध्यक्ष के बेतनों और भत्तों से है;

अनुच्छेद 208 से 211 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं);

अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) का परन्तुक और खण्ड (3) का परन्तुक और

अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) का उतना भाग जिसने का सम्बन्ध ज्ञापन सहित रिपोर्ट के राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है;

(iii) उक्त राज्य की विधान सभा एतद्वारा भग की जानी है।

(iv) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का शर्थ उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जाएगा और उम में गज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति किसी निदेश का, जहाँ तक उसका संबंध उसके छ़त्पो और उसकी शक्तियों से है, शर्थ, जब तक कि सदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, संसद के प्रति निदेश लगाया जाएगा और विशिष्टतया अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मंडल या उसके सदनों के प्रति निदेश का शर्थ ब्रमण।

राष्ट्रपति और संसद या उसके सदनों के प्रति निदेश लगाया जाएगा।

परन्तु इसमें की कोई वात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से अलग अनुच्छेद 159 नक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पंक्ति 1 से लेकर पंक्ति 4 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेंगी और न गण्ड्रपति को उम खंड के उपखंड (i) के अधीन उम सीमा तक जहाँ तक वह ठीक समझे उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेंगी;

(v) संविधान में राज्य के विधान मंडल के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदेश का ऐसे शर्थ लगाया जाएगा माना वह उन अधिनियमों और विधियों को भी समाविष्ट करता है जो इस उद्घोषणा के आधार पर संमद द्वारा या गण्ड्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपकंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं और मद्रास सामान्य खण्ड अधिनियम, 1891 (1891 का मद्रास अधिनियम 1) जैसा कि वह तमिल नाडु राज्य में प्रवृत्त है और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) का उतना भाग जितना राज्य की विधियों पर लागू है ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में इस प्रकार प्रभावी होगा मानों यह उस राज्य के विधान मंडल का अधिनियम हो।

नई दिल्ली :

31 जनवरी, 1976

फखरहुदीन अली अहमद,
राष्ट्रपति ।

[सं. फा. V / 11013 / 2 / ता. 76-एस एंड पी (डी-V)]

नई दिल्ली :

31 जनवरी, 1976

मुन्दर लाल खुराना,
सचिव ।

आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1976

सा० का० नि० 56 (ग्र)---राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सुननार्थ प्रकाशित किया जा रहा है ---

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज जनवरी, 1976 के हस्ताक्षरे दिन जारी की गई उद्धोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) का अनुसरण करते हुए एतद्वारा निम्न नाडु राज्य सरकार के सभी वृत्त्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उम राज्य के गजयाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियाँ, जिनको राष्ट्रपति न उक्त उद्घोषणा के खण्ड (क) के आधार पर न्वय सम्भाल लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के अधीन रखते हुए, उक्त राज्य के गजयाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

फ्रान्सीन अली अहमद,

राष्ट्रपति।

नई दिल्ली :

31 जनवरी, 1976

सुन्दर लाल खुराना,

सचिव।

नई दिल्ली :

31 जनवरी, 1976

